रणजीत टाइम्स
साप्ताहिक अख़बार

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे
वर्ष 14 | अंक 4 | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य - 2 रू.
RNI-NO.MPHIN/2015/64585

इंदौर प्रति मंगलवार, 16 जून 2026 से 22 जून 2026 तक

"भगवंत मान ने पंजाब को काले दौर से बाहर निकाला" : मोहाली में अकाली, भाजपा और कांग्रेस पर बरसे केजरीवाल

नगर निगम चुनाव में जनता ने विकास पर मुहर लगाई: आप नेता का दावा

पंजाब के मोहाली में आयोजित एक जनसभा में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब अब उस दौर से बाहर निकल चुका है, जहां भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का बोलबाला था। केजरीवाल ने मंच से कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और राज्य ने "काले दौर" से निकलकर विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीते साढ़े चार वर्षों में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं में सुधार के कई काम किए हैं।

मोहाली में नगर निगम चुनाव को लेकर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि जनता ने अपने वोट के माध्यम से सरकार के कामकाज पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि यह समर्थन दर्शाता है कि लोग अब पुराने राजनीतिक दलों की बजाय काम करने वाली राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। सभा में उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे केवल आलोचना की राजनीति कर रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर बदलाव के प्रयासों को नजरअंदाज किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में जो सुधार दिख रहे हैं, वे जनता के सहयोग और सरकार की नीतियों का परिणाम हैं।

इस रैली के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और आने वाले स्थानीय चुनावों को लेकर मुकाबला और अधिक रोचक होता दिख रहा है।

अखिलेश पहले बाबरी मस्जिद के चंदे का हिसाब दें: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला

अयोध्या में से जुड़े चढ़ावे और कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा सरकार पर लगाए गए सवालों के जवाब में राज्य के डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिस तरह राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी तरह अतीत में बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का भी हिसाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जवाबदेही सभी मामलों में समान रूप से होनी चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में मंदिर से जुड़े वित्तीय मामलों और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को लेकर माहौल पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक-दूसरे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिससे राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। इस मुद्दे ने एक बार फिर अयोध्या से जुड़े पुराने विवादों और उनके राजनीतिक प्रभाव को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

जयकारों से गूंजा कैंची धाम

स्थापना दिवस पर उमड़े लाखों भक्त

नैनीताल (उत्तराखंड): बाबा नीम करौली महाराज के पवित्र धाम कैंची धाम में स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन हुआ। पूरे क्षेत्र में "जय बाबा नीम करौली" के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया और लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला।

सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया।

प्रशासन की ओर से सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। भारी भीड़ के बावजूद व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई। स्थापना दिवस के अवसर पर भंडारे और प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कैंची धाम का यह वार्षिक आयोजन हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है और इस बार भी आस्था का सैलाब देखने को मिला।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट शुरू, उद्घाटन के साथ इतिहास रचा

नोएडा (जेवर): लंबे इंतजार के बाद आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) से पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भर दी। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में एविएशन कनेक्टिविटी का नया अध्याय शुरू हो गया है।

एयरपोर्ट का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर एयरपोर्ट को देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक बताया गया।

पहली कमर्शियल उड़ान इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित की गई, जो लखनऊ से नोएडा (जेवर) के लिए रवाना हुई। उड़ान के सफल संचालन के साथ ही एयरपोर्ट ने औपचारिक रूप से अपने कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू कर दिए। उद्घाटन समारोह में विशेष रूप से उन किसानों को भी शामिल किया गया जिन्होंने एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी। उन्हें इस ऐतिहासिक उड़ान का हिस्सा बनाकर सम्मानित किया गया।

इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली-एनसीआर में हवाई यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। शुरुआती चरण में यहां से कई प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले समय में इस एयरपोर्ट को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय एविएशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

लोकायुक्त का बड़ा ट्रैपः हाउसिंग बोर्ड का लेखापाल 4 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

छतरपुर। Lokayukta Police Madhya Pradesh ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए Chhatarpur में हाउसिंग बोर्ड के एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सागर लोकायुक्त की टीम ने हाउसिंग बोर्ड विभाग में पदस्थ संभागीय लेखापाल बी.पी. विश्वकर्मा को 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया।

इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक यह मामला हाउसिंग बोर्ड के मकान की रजिस्ट्री से जुड़ा है। फरियादी राम नारायण शुक्ला को विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत मकान नंबर 399 आवंटित किया गया था। मकान की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए उन्हें विभागीय औपचारिकताओं से गुजरना था। आरोप है कि इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बदले संभागीय लेखापाल बी.पी. विश्वकर्मा ने उनसे रिश्वत की मांग की।

बताया जा रहा है कि आरोपी लेखापाल ने रजिस्ट्री की फाइल आगे बढ़ाने के लिए कुल 6 हजार रुपये मांगे थे। फरियादी लगातार दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा था। बार-बार की मांग और परेशानियों से तंग आकर राम नारायण शुक्ला ने इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद Lokayukta Police Sagar ने पूरे मामले का सत्यापन किया। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की तैयारी की। अधिकारियों ने फरियादी को निर्देश दिए और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछाया। तय योजना के तहत जैसे ही फरियादी ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 4 हजार रुपये आरोपी बी.पी. विश्वकर्मा को सौंपे, उसी समय पहले से निगरानी कर रही लोकायुक्त टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रासायनिक घोल से आरोपी के हाथ धुलवाए गए, जिसमें उसके हाथ गुलाबी हो गए। यह रिश्वत लेने का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है।

लोकायुक्त अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस मामले में अन्य कोई अधिकारी या कर्मचारी भी शामिल है। इस कार्रवाई के बाद हाउसिंग बोर्ड विभाग में हलचल मच गई है। विभागीय कर्मचारियों में इस बात को लेकर चिंता है कि लोकायुक्त की जांच आगे और किन स्तरों तक पहुंच सकती है। सूत्रों के मुताबिक कई अन्य मामलों की भी जांच की जा सकती है, जहां आम नागरिकों को अपने वैध कार्यों के लिए रिश्वत देने को मजबूर किया जाता है। मध्यप्रदेश में हाल के महीनों में लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार तेज हुई है। अलग-अलग जिलों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां अब अधिक सक्रिय हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हाउसिंग, राजस्व, नगर प्रशासन और पंजीयन विभाग जैसे क्षेत्रों में आम नागरिकों को अक्सर

हाई कोर्ट के आदेश पर भिलाई में

अवैध निर्माण हटाया गया, गरीबों के लिए आवास परियोजना का रास्ता साफ

नगर निगम की कार्रवाई में अवैध रूप से निर्मित मदरसा ध्वस्त, भूमि का होगा सार्वजनिक उपयोग

CONSTITUTION
LAW
JUSTICE

छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक अवैध रूप से निर्मित मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई राधिका नगर क्षेत्र में की गई, जहां लंबे समय से भूमि के उपयोग और निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार न्यायालय के निर्देशों के पालन में अवैध निर्माण को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि पर अब गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आवासीय परियोजना विकसित करने की योजना है, जिससे पात्र लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। नगर निगम का दावा है कि भूमि का उपयोग अब जनहित से जुड़ी योजनाओं के लिए किया जाएगा। आवास परियोजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घर निर्माण की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहर में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों तथा नियमों के विपरीत निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं, इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल नगर निगम और प्रशासन का फोकस न्यायालय के आदेशों के अनुपालन और प्रस्तावित आवास योजना को आगे बढ़ाने पर है।

मोहन भागवत के कार्यक्रम में पहुंचे 3 कुलपति विवादों में, केरल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उठाए सवाल

संघ के मंच पर मौजूदगी को लेकर छिड़ी राजनीतिक बहस, भाजपा ने आरोपों को बताया तुष्टीकरण की राजनीति केरल में तीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कार्यक्रम में Mohan Bhagwat की मौजूदगी के बीच कुलपतियों की भागीदारी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सवाल उठाए हैं। विवाद उस समय बढ़ गया जब राज्य की राजनीति में इस मुद्दे को विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और संवैधानिक पदों की निष्पक्षता से जोड़कर देखा जाने लगा।

विपक्षी दलों के साथ-साथ सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने भी कुलपतियों के इस कार्यक्रम में शामिल होने पर आपत्ति जताई और स्पष्टीकरण की मांग की।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विवाद में जिन कुलपतियों के नाम सामने आए हैं, उनमें Mohan Kunnummal, Ciza Thomas और K. Sivaprasad शामिल बताए जा रहे हैं। इनकी कार्यक्रम में मौजूदगी को लेकर राजनीतिक दलों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। विवाद बढ़ने के बाद भाजपा ने भी मोर्चा संभाल लिया। भाजपा के केरल प्रदेश अध्यक्ष Rajeev Chandrasekhar ने आलोचनाओं पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी शैक्षणिक कार्यक्रम या वैचारिक मंच में भाग लेना गलत नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार और विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं का कहना है कि कुलपतियों को विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने की स्वतंत्रता है, जबकि विरोधी दलों का तर्क है कि संवैधानिक और शैक्षणिक पदों पर बैठे लोगों को राजनीतिक या वैचारिक विवादों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस मुद्दे ने केरल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मामला विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार और राजनीतिक दलों के बीच बहस का बड़ा विषय बना रह सकता है।

रणजीत टाइम्स
साप्ताहिक अख़बार
इंदौर प्रति मंगलवार, 16 जून 2026 से 22 जून 2026 तक

प्रतिभा सम्मान समारोह-वर्ष 7 में संघर्षशील विद्यार्थियों का हुआ भव्य सम्मान, शिक्षा के प्रति समर्पण को मिला मंच

राजेश धाकड़

इंदौर। स्प्रेडिंग स्माइल्स संस्था द्वारा आयोजित "प्रतिभा सम्मान समारोह-वर्ष 7" का भव्य एवं प्रेरणादायी आयोजन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर आर्थिक रूप से कमजोर, श्रमिक एवं मध्यमवर्गीय परिवारों से आने वाले उन मेधावी एवं संघर्षशील विद्यार्थियों का सम्मान किया गया, जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर सफलता अर्जित की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उपस्थित रहे। उनके साथ इंदौर लोकसभा सांसद शंकर लालवानी, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, पूर्व महापौर कृष्णमुरारी मोघे, भाजपा नगर मंत्री स्वाति काशीद, भाजपा नगर मंत्री नेहा शर्मा, विधानसभा-5 के विधायक महेंद्र हार्डिया, एमआईसी सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया, पूर्व आईपीएस अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी, वरिष्ठ समाजसेवी गणेश चौधरी, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष सम पावरी, समाजसेवी राहुल जैन, समाजसेवी अमित चावला, भाजपा नेता मनोज परमार सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सम्मान-पत्र प्रदान कर उनके परिश्रम और उपलब्धियों का सम्मान किया गया। साथ ही शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से लैपटॉप, साइकिल एवं अन्य उपयोगी उपहार लॉटरी प्रणाली के माध्यम से वितरित किए गए। उपहार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के चेहरे पर झलकती खुशी और उत्साह ने पूरे समारोह को यादगार बना दिया। संस्था के संरक्षक अशोक अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि, "हम मानते हैं कि हर बच्चे की मेहनत सम्मान की हकदार है। समाज में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो अभावों के बीच रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिभा सम्मान का उद्देश्य केवल अंकों का सम्मान करना नहीं, बल्कि संघर्ष, लगन और शिक्षा के प्रति समर्पण को पहचान देना है। जब किसी विद्यार्थी को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है।"

संस्था के अध्यक्ष राहुल लोदवाल ने कहा कि, "श्रमिक बस्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के सपनों को उड़ान देना ही स्प्रेडिंग स्माइल्स का मूल उद्देश्य है। कई माता-पिता दिनभर कठिन मेहनत कर अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। यह सम्मान केवल विद्यार्थियों का नहीं, बल्कि उनके माता-पिता के त्याग, संघर्ष और उम्मीदों का भी सम्मान है। हमें विश्वास है कि आज सम्मानित हुए विद्यार्थी भविष्य में समाज और देश का नाम रोशन करेंगे।" उन्होंने बताया कि संस्था पिछले सात वर्षों से शिक्षा, सामाजिक जागरूकता एवं प्रतिभा प्रोत्साहन के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। संस्था अब तक हजारों विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का कार्य कर चुकी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, पत्रकार साथी एवं नागरिक उपस्थित रहे। पूरे आयोजन ने यह संदेश दिया कि सफलता केवल बड़े अंकों से नहीं मापी जाती, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानकर आगे बढ़ने का साहस, संघर्ष और शिक्षा के प्रति समर्पण ही वास्तविक प्रतिभा की पहचान है।

प्रतिभा सम्मान समारोह – वर्ष 7 न केवल विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, बल्कि समाज को भी यह संदेश देने में सफल रहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और उज्ज्वल भविष्य की राह प्रशस्त करती है।

मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2026: इंदौर में 120 प्रतिभावान छात्र-छात्राएं सम्मानित

शिक्षाविदों और समाजसेवियों ने विद्यार्थियों को दी उज्ज्वल भविष्य की प्रेरणा

इंदौर। आजाद माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन, आजाद नगर द्वारा "मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2026" का भव्य आयोजन किया गया। इस गौरवशाली समारोह में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लगभग 120 मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ तिलावत-ए-कुरआन से हुआ। इसके बाद संस्था के सचिव अब्दुल हफीज बनारसी ने एसोसिएशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। इस गरिमामयी समारोह में मुख्य रूप से शहर काजी डॉ. इशरत अली, हाजी शफी शेख, एडवोकेट मयूरी जैन, एडवोकेट शारिब खान, शेख शाकिर, सलमान हाशमी, अंसार पटेल और डॉ. अनीस सहित अनेक शिक्षाविद, समाजसेवी और विभिन्न स्कूलों के संचालक उपस्थित रहे।

AZAD MINORITY
SCHOOLS ASSOCIATION
MERITORIOUS STUDENTS

समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने विद्यार्थियों को सफलता के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और नैतिक शिक्षा का महत्व समझाया तथा उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन अब्दुल हफीज बनारसी, जावेद खान और रमीज़ खान ने संयुक्त रूप से किया। समारोह के समापन पर रागिब अहमद चौधरी ने सभी अतिथियों, शिक्षकों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षकगण और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। यह समारोह शिक्षा, प्रतिभा सम्मान और आपसी सौहार्द का एक अनूठा और प्रेरणादायक उदाहरण बनकर संपन्न हुआ।

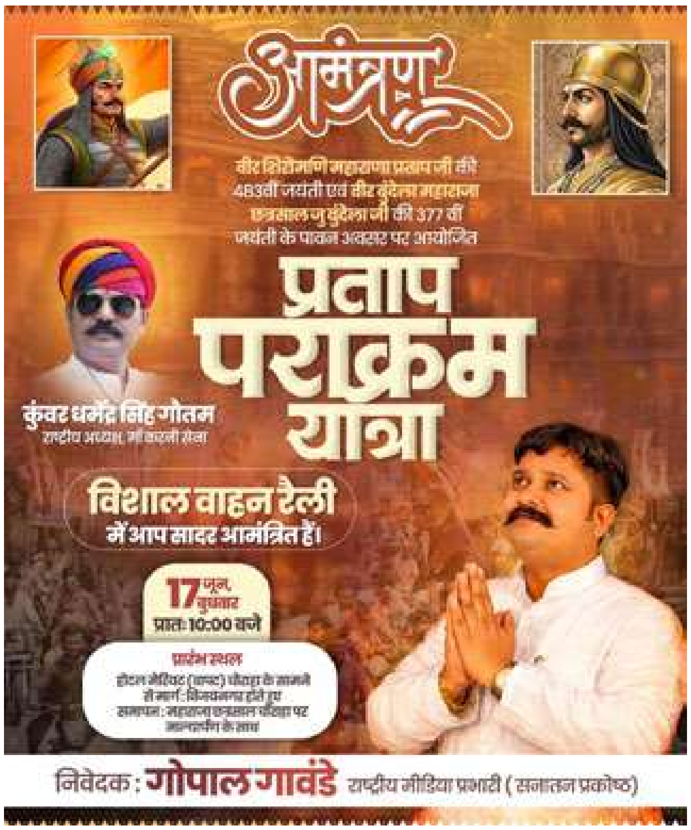
आमंत्रण
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती एवं वीर बुंदेला महाराजा छत्रसाल जू बुंदेला जी की 377 वीं जयंती के पावन अवसर पर आयोजित
प्रताप पराक्रम यात्रा
कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम
राष्ट्रीय अध्यक्ष, माँ करणी सेना
विशाल वाहन रैली
में आप सादर आमंत्रित हैं।
17 जून, बुधवार
प्रातः 10:00 बजे
प्रारंभ स्थल
निवेदक : गोपाल गावंडे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी (सनातन प्रकोष्ठ)

सहजयोग मस्तिष्क परे जाकर विकसित होना है : श्री माताजी

श्री माताजी निर्मला देवी जी द्वारा प्रतिस्थापित सहजयोग ध्यान की वो सनातन पद्धति है जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों व चिकित्सकों ने भी स्वीकार किया है। मनुष्य की जिन शारीरिक व मानसिक जटिलताओं को आधुनिक विज्ञान समझ नहीं सका उन्हें सहजयोग द्वारा समझाया गया है। विभिन्न शारीरिक रोगों में, मानसिक तनाव को दूर करने में, कृषि का उत्पादन बढ़ाने में, वातावरण की नकारात्मकता को दूर करनेमें सहजयोग ने अवर्णनीय प्रभाव दिखाया है। परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कहीं व्यापक है यह आत्मा के परमात्मा से योग का साधन है इसके पश्चात समस्त बाधाएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। यह जीवंत अनुभव है जिसे पढ़कर नहीं समझा जा सकता सहजयोग विवेक व बोध के द्वारा क्रिया एवं विचारों से बाहर निकाल कर ध्यान का मार्ग प्रशस्त करता है। और हमें उस ज्ञान व विद्या का साक्षात्कार प्रदान करता है जो हमारे साथ जन्मी है, जो सहज है। श्री माताजी ने अपनी अमृतवाणी में वर्णित किया है कि,

"सहजयोग को मानसिक न बनाएं। आप इसे मानवीय चेतना के माध्यम से नहीं समझ सकते। मैंने आपको सैंकड़ों बार कहा है कि आप अपने दिमाग की सीमित क्षमता से सहजयोग को नहीं समझ सकते। अपने हृदयों को खोलें।.. आपको सहजयोग में विकसित होना होगा। यह समझ लें कि आपको अपने दिमाग के पार जाकर विकसित होना है। अपने मस्तिष्क या बुद्धि से, अगर हम समझ पाते, या हम अपना उत्थान पा लेते, तो यह इसे पाने का सबसे आसान तरीका होता। लेकिन नहीं, प्रत्येक मानव के पास एक सीमित सोच वाला दिमाग है। तो कोई इस ओर जाता है। कोई उस तरफ जाता है। कोई उस तरफ जाता है। और इसी तरह हमारे सामने युद्धों की समस्या है। हमारी समस्या यह है कि हर किसी का दृष्टिकोण अलग-अलग होता है। (18 जुलाई 1994) परंतु शाश्वत सत्य एक है अतः अपने आप को इस भ्रम, संदेह व भटकाव से बाहर निकल कर सत्य के अनुभव का एक अवसर अवश्य प्रदान करें।ध्यान की इस वैज्ञानिक एवं पूर्णतः निःशुल्क पद्धति की अधिक जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 18002700800 अथवा www.sahajayoga.org.in पर संपर्क करें।

डिजिटल डाकघर का दम, लेकिन पोस्टल ऑर्डर हुआ गुम!

भारतीय डाक
डाक सेवा जन सेवा
भारतीय डाक
India Post
करैरा
KARERA
473660

हेमंत कुमार भार्गव

करैरा में उपभोक्ता लगा रहे चक्कर, जिम्मेदार बेखबर करैरा। एक ओर केंद्र सरकार और केंद्रीय संचार मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से देशभर के डाकघरों का आधुनिकीकरण कर उन्हें डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर करैरा उप डाकघर में एक बुनियादी सेवा पोस्टल ऑर्डर की अनुपलब्धता उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। जानकारी के अनुसार करैरा उप डाकघर में लंबे समय से 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध नहीं है। जब इस संबंध में उप डाकघर के जिम्मेदार कर्मचारियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि इसके लिए हेड ऑफिस शिवपुरी से संपर्क किया जाए। वहीं शिवपुरी स्तर पर भी पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध न होने की बात सामने आई।

स्थानीय उपभोक्ताओं* भारत कुमार शर्मा का कहना है कि उन्हें पोस्टल ऑर्डर लेने के लिए कई-कई बार उप डाकघर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें यही जवाब मिलता है कि पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध नहीं हैं।

हेमंत कुमार* उपभोक्ताओं ने बताया कि वे दस-दस बार उप डाकघर पहुंचे, लेकिन एक बार भी उन्हें पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल सका।

***डाकघरों में डिजिटल सुविधाएं तो हैं, लेकिन मूलभूत सेवा गायब**- विडंबना यह है कि डाक विभाग डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन और आधुनिक सेवाओं का प्रचार-प्रसार कर रहा है, लेकिन आज भी अनेक शासकीय और वैधानिक कार्यों में उपयोग होने वाला पोस्टल ऑर्डर उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों को डिजिटल सुविधा के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर नजर आ रहा है।

हकीकत

"डाकघर अब डिजिटल हो गए हैं, कंप्यूटर चमक रहे हैं, इंटरनेट दौड़ रहा है, लेकिन पोस्टल ऑर्डर शायद किसी डिजिटल फाइल में अटक गया है। उपभोक्ता काउंटर पर खड़े हैं और जवाब मिल रहा है—'हेड ऑफिस में पूछ लो'। सवाल यह है कि जब एक साधारण पोस्टल ऑर्डर की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही, तो फिर आम आदमी आखिर अपनी शिकायत किस डाक से भेजे?" स्थानीय नागरिकों ने डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि करैरा सहित जिले के सभी उप डाकघरों में पोस्टल ऑर्डर की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

अवैध रेत माफियाओं पर करैरा पुलिस का शिकंजा, ओवरलोड रेत से भरे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

हेमंत भार्गव

करैरा। पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भुटिया के निर्देश पर जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत करैरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत से भरे दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा माना जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उईके के निर्देशन एवं एसडीओपी प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना करैरा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि झंडा एवं गदाई के बीच आम रोड पर दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अवैध बजरी (रेत) से भरी खड़ी हैं। सूचना पर थाना करैरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बॉडी से ऊपर तक ओवरलोड रेत से भरी मिलीं। पुलिस द्वारा चालकों की तलाश की गई, लेकिन वे मौके से फरार मिले। पुलिस ने मौके से एक लाल रंग का स्वराज 855 ट्रैक्टर एवं एक नीले रंग का न्यू हॉलैंड 3630 ट्रैक्टर मय ट्रॉली जब्त किया। दोनों ट्रॉलियों में क्षमता से अधिक रेत भरी हुई थी। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने तथा अवैध परिवहन की पुष्टि होने पर पुलिस ने दोनों वाहनों को विधिवत जब्त कर लिया। पुलिस ने वाहन स्वामियों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण खनिज विभाग शिवपुरी को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेज दिया है। मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

जब्त वाहन

स्वराज 855 ट्रैक्टर मय ट्रॉली

न्यू हॉलैंड 3630 ट्रैक्टर मय ट्रॉली

भाजपा का ग़ज़ब मीडिया संवाद....?

राजेश धाकड़

भोपाल के मिंटो हॉल में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक भव्य "मीडिया संवाद" का आयोजन किया गया। मंच सजा था, कुर्सियाँ सजी थीं, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद थी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपलब्धियों का पुलिंदा लेकर उपस्थित थे। उन्होंने सरकार की बारह वर्षों की उपलब्धियाँ गिनाईं। उपलब्धियाँ भी ऐसी-ऐसी कि कुछ देर के लिए लगा मानो बुद्धिजीवियों को बुद्धू बनाने का कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा हो। वैसे "संवाद" शब्द का अर्थ होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों का आदान-प्रदान। संवाद का मतलब सवाल और जवाब दोनों होता है। संवाद का उद्देश्य समझ बढ़ाना, जिज्ञासाओं का समाधान करना और विभिन्न पक्षों को सुनना होता है। लोकतंत्र में मीडिया संवाद का अर्थ तो और भी व्यापक है, जहाँ पत्रकार जनता की ओर से सत्ता से सवाल करते हैं और सत्ता जवाब देती है। लेकिन भोपाल में आयोजित इस अद्भुत "मीडिया संवाद" ने संवाद की सारी पारंपरिक परिभाषाओं को नया रूप दे दिया। यहाँ संवाद कम और प्रवचन अधिक था।

पत्रकारों के कैमरे भीतर नहीं गए। मोबाइल फोन पर निगाहें थीं। रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं थी। सवाल पूछने की अनुमति नहीं थी। केवल बैठकर सुनना था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पत्रकार किसी प्रेस वार्ता में नहीं बल्कि किसी विशेष आध्यात्मिक कथा के श्रोता बनकर आए हों, जहाँ कथा वाचक बोलेंगे और श्रोता केवल सिर हिलाकर श्रद्धा प्रकट करेंगे। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन यहाँ स्तंभ बनने से पहले ही उसे दर्शक दीर्घा में बैठा दिया गया। सबसे रोचक प्रसंग तो यह रहा कि यदि कोई काली शर्ट पहनकर पहुँच गया तो उसके प्रवेश पर भी सवाल खड़े हो गए। अब तक हमने नेताओं की नाकाबंदी, विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी और अघोषित आपातकाल जैसे शब्द सुने थे, लेकिन पत्रकारों की "वस्त्रबंदी" का यह नया अध्याय भी देखने को मिल गया। लगता है अब लोकतंत्र में विचारों के साथ-साथ रंगों की भी राजनीतिक वैधता तय की जाने लगी है। मीडिया संवाद में पत्रकारों की भूमिका वही थी जो रेडियो पर "मन की बात" सुनते समय श्रोताओं की होती है। फर्क सिर्फ इतना था कि वहाँ रेडियो होता है और यहाँ मंत्री महोदय स्वयं उपस्थित थे। सुनना अनिवार्य था, पूछना वर्जित था और रिकॉर्ड रखना भी लगभग अपराध जैसा प्रतीत हो रहा था।

अब प्रश्न यह है कि यदि पत्रकार सवाल नहीं पूछेंगे तो संवाद किस बात का? यदि कैमरे नहीं जाएंगे तो पारदर्शिता कहाँ है? यदि रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो जवाबदेही कैसे तय होगी? और यदि केवल उपलब्धियाँ ही सुनाई जाएँगी तो फिर उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कहा जाए? उसे सीधे-सीधे "सरकारी उपलब्धि पाठ" नाम दे दिया जाए।

संभवतः आयोजकों को डर रहा होगा कि कहीं कोई असुविधाजनक प्रश्न माहौल खराब न कर दे। क्योंकि प्रश्नों की एक बुरी आदत होती है वे तथ्यों की मांग करते हैं। और कभी-कभी तथ्य भाषणों के साथ सहज नहीं बैठते। देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल हैं, बेरोज़गारी पर सवाल हैं, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सवाल हैं, नई शिक्षा नीति के प्रभाव पर सवाल हैं। स्वाभाविक था कि पत्रकार इन विषयों पर प्रश्न पूछते। लेकिन संवाद में प्रश्नों की जगह यदि केवल प्रशंसा का अधिकार हो, तो फिर वह संवाद नहीं, एकतरफ़ा प्रसारण बन जाता है। लोकतंत्र में सत्ता को सवालों से डरना नहीं चाहिए। सवाल विरोध नहीं होते, बल्कि जवाबदेही का माध्यम होते हैं। जिस दिन सत्ता सवालों को शत्रु समझने लगे और पत्रकारों को केवल श्रोता, उस दिन संवाद की आत्मा घायल हो जाती है।

भोपाल का यह आयोजन शायद आने वाले समय की पत्रकारिता का नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जहाँ पत्रकार आएँ, बैठें, सुनें, ताली बजाएँ और धन्यवाद देकर लौट जाएँ। न कोई प्रश्न, न कोई प्रतिप्रश्न, न कोई असहमति। और यदि यही पत्रकारिता का भविष्य है, तो फिर चिंता केवल मीडिया की नहीं, लोकतंत्र की भी है। क्योंकि जिस लोकतंत्र में संवाद की जगह प्रवचन ले ले, वहाँ प्रश्न पूछने वालों की संख्या कम होने लगती है और सुनने वालों की भीड़ बढ़ने लगती है।

बाकी भोपाल में पत्रकारिता की हालत देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि वह अभी आईसीयू में है, कुछ लोग उसे वेंटिलेटर पर मान रहे हैं, और कुछ लोग उसकी नब्ज़ टटोलकर अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कभी फिर कोई वास्तविक "मीडिया संवाद" देखने को मिले जहाँ पत्रकार सवाल पूछ सकें और सत्ता जवाब देने का साहस दिखा सके।

बामौरकलां: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत

अतुल जैन

खनियांधाना। तहसील के बामौरकलां थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंचनपुरा मोहल्ला के पास एक दुखद सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक विनोद अहिरवार (उम्र 40 वर्ष), जो गोराकलां, थाना चंदेरी के निवासी थे, बाइक (क्रमांक MP67MK0163) से कहीं जा रहे थे। 14 जून 2026 की सुबह लगभग 5:00 बजे कंचनपुरा मोहल्ला, पिछोर-चंदेरी रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विनोद अहिरवार की पीठ में गंभीर चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

घटना की सूचना फरियादी चंदन अहिरवार (निवासी आजादनगर, बामौरकलां) को विनोद अहिरवार के मोबाइल से मिली। सूचना मिलते ही चंदन अहिरवार और सौरभ अहिरवार तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने विनोद अहिरवार को मृत अवस्था में पाया। इसके बाद मृतक के पुत्र जयदेव और सहदेव अहिरवार तथा अन्य परिजन भी मौके पर पहुँच गए। परिजनों द्वारा घटना की सूचना थाना बामौरकलां को दी गई। पुलिस ने फरियादी चंदन अहिरवार की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 79/2026, धारा 106(1) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से विवेचना कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों या अन्य साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। इस दुखद घटना के संबंध में आगे की कानूनी कार्यवाही और जाँच जारी है।

झाबुआ पुलिस की मुस्तैदी: 2.52 लाख की साइबर ठगी करने वाला आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार

सलीम हुसैन

झाबुआ। थाना थांदला पुलिस ने तत्परता, तकनीकी दक्षता एवं साइबर इनपुट के प्रभावी उपयोग से ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का मात्र तीन दिनों में खुलासा करते हुए आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अन्य खातों में ट्रांसफर किए गए 2,06,493 की रकम भी होल्ड कराकर सुरक्षित कराई है। सस्ते मोबाइल का झांसा देकर की 2.52 लाख की ठगी घटना 6 जून 2026 की है। जवाहर मार्ग, थांदला निवासी एवं मोबाइल शॉप संचालक रवि पिता प्रकाशचंद्र गादिया को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कॉल किया गया। आरोपी ने स्वयं को मोबाइल का बड़ा डीलर बताते हुए वीवो कंपनी के 20 मोबाइल फोन कम कीमत पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। आरोपी के झांसे में आकर फरियादी ने कुल 2,52,680 की डील तय की तथा आरोपी के बैंक खाते में निम्नानुसार राशि स्थानांतरित की—

- **RTGS के माध्यम से:** 1,92,000
- **PhonePe के माध्यम से:** 60,680

राशि प्राप्त होते ही आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। स्वयं के साथ धोखाधड़ी होने का एहसास होने पर फरियादी ने तत्काल थाना थांदला पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना थांदला में अपराध क्रमांक 323/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) एवं 319(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

महाराष्ट्र के पालघर से आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में साइबर सेल झाबुआ एवं थाना थांदला की संयुक्त टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई। थाना प्रभारी थांदला के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को तत्काल पालघर (महाराष्ट्र) रवाना किया गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी रोशन पिता राजेंद्र शर्मा, निवासी ओल्ड मनोहर रोड, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, थाना एवं जिला पालघर (महाराष्ट्र) को गिरफ्तार किया। पूछताछ एवं बैंक खातों की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ठगी की राशि को विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहा था। इस पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक समन्वय के माध्यम से अन्य खातों में ट्रांसफर किए गए 2,06,493 की रकम भी होल्ड कराकर सुरक्षित कराई है। मामले में आगे की जांच जारी है।

देशभक्ति - जनसेवा
पुलिस थाना थान्दला
जिला झाबुआ (म.प्र.) मो. 7587616949

फिशिंग श्रेणी का साइबर फ्रॉड -

प्रारंभिक जांच में यह मामला फिशिंग एवं ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की श्रेणी का पाया गया है, जिसमें आरोपी आकर्षक ऑफर, लालच या झूठे व्यापारिक प्रस्ताव देकर लोगों से ऑनलाइन माध्यम से राशि प्राप्त कर लेते हैं और बाद में संपर्क समाप्त कर देते हैं।

झाबुआ पुलिस की अपील -

झाबुआ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में आकर बड़ी ऑनलाइन राशि का लेन-देन न करें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस थाना, साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल(NCRP) पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते राशि को होल्ड कर नुकसान को कम किया जा सके।

महू गांव नगर पंचायत अनुसूचित जाति विभाग द्वारा कांग्रेस जनों का स्नेह सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया

कार्यक्रम के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र मालवीय जी के मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गदर्शन हरिराम चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । प्रारंभ में बाबा साहब अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया इस अवसर पर पर संगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ज्वाला प्रसाद बामनिया,, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के उपाध्यक्ष द्वय रणजीत गोहर,, डॉक्टर सीता राम गोयल जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष विजय बिलोनिया जी धार जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के आनन्द करोले पीथमपुर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉ हेमंत हीरोले जिला महिला उत्पीडन कांग्रेस अध्यक्ष मोनिका सोलंकी,, जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री दौलत पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विष्णु मालवीय मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान,,नवल पटेल गौरव सोलंकी विवेक सकोरिया प्रवीण पाटिल गोविंद मालवीय कैलाश परमार बाबुलाल राठौर रामचंद्र राठौर जगमोहन सोन नरेश जोशी उदय सिंह चौहान मुकेश चौहान कैलाश सालवी आदि नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं उपस्थित थे । सभी सम्माननीय अतिथियों ने मोदी सरकार की भ्रष्टाचारी नितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान सरकार मंहगाई शिक्षा नीति और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था कों समाप्त कर रही । आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कामयाबी हासिल करने के कांग्रेस की रीति नीति को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को पहुंचाने का आह्वाहन किया । इस अवसर पर मार्गदर्शक हरिराम चौहान का सभी सम्माननीय अतिथियों ने सम्मान किया ।वरिष्ठ नेता हरिराम चौहान ने कबीर भजन के माध्यम से मोदी सरकार पर निशाना साधा।संचालन आशिष वर्मा ने किया आभार प्रवीण पाटिल ने व्यक्त किया।

भाजपा का बढ़ता राजनीतिक वर्चस्वः दो सीटों से तीन-चौथाई भारत की सत्ता तक का सफर

नई दिल्ली। भारतीय राजनीति में Narendra Modi के नेतृत्व में Bharatiya Janata Party का लगातार विस्तार अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन चुका है। केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के साथ भाजपा का 13वें वर्ष में प्रवेश केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा अध्याय माना जा रहा है। यह वही पार्टी है जिसने 1984 के लोकसभा चुनाव में केवल दो सीटों से शुरुआत की थी और आज देश के 22 राज्यों में या तो उसकी सरकार है या उसके नेतृत्व वाले गठबंधन की सत्ता कायम है। भाजपा का यह सफर संघर्ष, रणनीति और वैचारिक विस्तार का मिश्रण रहा है। जनसंघ के दौर से लेकर आज तक पार्टी ने कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे। 1980 में जनसंघ ने भाजपा के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन शुरुआती दौर आसान नहीं था। 1984 में Indira Gandhi की हत्या के बाद पैदा हुई सहानुभूति लहर में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और भाजपा महज दो सीटों तक सीमित रह गई। उस दौर में Atal Bihari Vajpayee और Lal Krishna Advani जैसे बड़े नेताओं के बावजूद पार्टी को जनाधार बढ़ाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1989 के चुनाव में बोफोर्स घोटाले ने कांग्रेस की साख को कमजोर किया और भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाने का अवसर मिला। इसी समय मंडल और कमंडल की राजनीति ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। V. P. Singh और Devi Lal के बीच सत्ता संघर्ष ने सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण को तेज किया, जिसका लाभ भाजपा को मिला। 1991 में Rajiv Gandhi की हत्या के बाद कांग्रेस सत्ता में तो लौटी, लेकिन भाजपा पहली बार 120 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी। यह भाजपा के राष्ट्रीय उभार का निर्णायक मोड़ था।

वैश्विक मंदी के बीच भारत की रफ्तार

चुनौतियों के दौर में विकास का नया अध्याय

दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय अनिश्चितताओं और संकटों के दौर से गुजर रही है। वैश्विक स्तर पर युद्ध, महंगाई, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं, ऊर्जा संकट और व्यापारिक तनावों ने विकास की गति को प्रभावित किया है। इसी बीच World Bank की ताजा रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में वैश्विक विकास दर घटकर 2.5 प्रतिशत तक सीमित रह सकती है। हालांकि इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भारत 6.6 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह स्थिति भारत की आर्थिक मजबूती और नीतिगत स्थिरता को दर्शाती है।

नई दिल्ली। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटल क्रांति, कर सुधार, आधारभूत ढांचे के विकास और विनिर्माण विस्तार के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दिया है। Narendra Modi सरकार की 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' नीति का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 7.7 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक रही। यह आंकड़ा बताता है कि घरेलू मांग, औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्र में निरंतर मजबूती बनी हुई है।

भारत की अर्थव्यवस्था की यह मजबूती ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और सरकार पर सब्सिडी का दबाव भी बढ़ा है। इसके बावजूद देश की आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बनी रहना यह साबित करता है कि आर्थिक ढांचा पहले की तुलना में अधिक लचीला और मजबूत हुआ है। हालांकि आने वाले समय में चुनौतियां और गंभीर हो सकती हैं। कमजोर मानसून, सूखे की आशंका, महंगाई का दबाव, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और घरेलू मांग में कमी जैसे कारक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।

इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जीवन स्तर को बेहतर बनाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को कम करने, आर्थिक सुधारों को गति देने और उद्योग-व्यापार की सुगमता बढ़ाने जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा की गई। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि वैश्विक संकटों के बीच भारत अपनी आर्थिक गति बनाए रखे और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करे। भारत की आर्थिक रणनीति में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) इस समय सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने घोषणा की है कि भारत अगले 10 महीनों में नौ नए एफटीए लागू करेगा। इनमें सबसे अधिक चर्चा अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते की है, जो अगले महीने के मध्य तक अंतिम रूप ले सकता है। यदि यह समझौता होता है तो भारत के निर्यात, निवेश और विनिर्माण क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी।

इस समय वैश्विक निर्यात में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन भारत का प्रदर्शन इसके विपरीत है। अप्रैल और मई 2026 के दौरान भारत का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत बढ़ा है। यह संकेत है कि भारत वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसका बड़ा कारण वे व्यापार समझौते हैं, जो बीते वर्षों में किए गए। भारत ने United Arab Emirates, Mauritius, Australia और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) के देशों — Switzerland, Norway, Iceland और Liechtenstein — के साथ जो समझौते किए हैं, उनका लाभ अब दिखने लगा है। हाल ही में Oman के साथ लागू व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) से भी भारत को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में भारत और ओमान के बीच व्यापार दोगुना होकर 20 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है।

इस समझौते से कृषि, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, दवाइयां, वस्त्र, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग उत्पाद और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही यह समझौता दक्षिण एशिया, खाड़ी क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ने वाले एक रणनीतिक आर्थिक गलियारे का आधार बनेगा। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारत की एफटीए नीति तेजी से विस्तार कर रही है। हाल ही में New Zealand के साथ भी एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जो जल्द लागू होगा। इसके अलावा European Union और United Kingdom के साथ हुए व्यापार समझौतों का क्रियान्वयन भी इसी वर्ष संभावित है। इसके अलावा भारत Canada, Israel, Russia, Peru, Chile, South Africa और Mexico के साथ भी बातचीत कर रहा है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इन समझौतों का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक विनिर्माण और निवेश केंद्र के रूप में उभर सकता है। लेकिन इसके लिए केवल समझौते करना ही पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और सरल बनाना होगा। साथ ही बजट में तय 80 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ाना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और कृषि क्षेत्र की आय बढ़ेगी। भारत के सामने अवसर और चुनौतियां दोनों मौजूद हैं। एक ओर वैश्विक मंदी और आर्थिक अनिश्चितताएं हैं, तो दूसरी ओर घरेलू सुधारों और व्यापारिक समझौतों के जरिए नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। सेवा क्षेत्र, मैन्यूफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत आधार पर भारत इस वित्त वर्ष में सात प्रतिशत के आसपास विकास दर बनाए रख सकता है।

स्पष्ट है कि भारत अब केवल वैश्विक संकटों का सामना करने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया की आर्थिक दिशा तय करने वाली प्रमुख शक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में सरकार की नीतियों, वैश्विक साझेदारियों और घरेलू सुधारों की सफलता ही यह तय करेगी कि भारत इस आर्थिक अवसर को कितनी दूर तक ले जा पाता है।

चेन्नई बना भारत का औद्योगिक पावरहाउस: जहां बनती हैं कारें, ट्रेनें और रक्षा उपकरण

नई दिल्ली। भारत तेजी से वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन के केंद्र में एक शहर सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरा है — Chennai। अक्सर जब देश के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों की बात होती है तो Kanpur, Indore, Pune और Ahmedabad जैसे नाम सामने आते हैं, लेकिन फैक्ट्रियों की संख्या, उत्पादन क्षमता और औद्योगिक विविधता के मामले में चेन्नई ने खुद को देश का सबसे बड़ा "फैक्ट्रियों का शहर" साबित किया है। यही वजह है कि इसे भारत का 'डेट्रायट' कहा जाता है। भारत की औद्योगिक प्रगति में चेन्नई की भूमिका लगातार मजबूत हुई है। खासकर ऑटोमोबाइल, भारी इंजीनियरिंग, रक्षा उत्पादन, रेलवे कोच, इलेक्ट्रॉनिक्स और चमड़ा उद्योग में इस शहर की पकड़ इतनी मजबूत है कि यह देश की आर्थिक रीढ़ का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। चेन्नई और इसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्र जैसे Sriperumbudur और Oragadam देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में विकसित हो चुके हैं।

वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार Tamil Nadu में कुल 40,121 फैक्ट्रियां दर्ज की गईं, जो पूरे देश में सबसे अधिक हैं। इस उपलब्धि में चेन्नई का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। औद्योगिक विशेषज्ञों का कहना है कि चेन्नई की भौगोलिक स्थिति, मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और पोर्ट कनेक्टिविटी ने इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आदर्श शहर बना दिया है। चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर है। देश में बनने वाली लगभग एक-तिहाई गाड़ियां यहीं तैयार होती हैं। यही कारण है कि इसे अमेरिका के प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल शहर डेट्रायट की तर्ज पर "इंडियाज डेट्रायट" कहा जाता है। यहां Hyundai Motor Company, BMW, TVS Motor Company, Renault, Nissan Motor Corporation और Daimler Truck जैसी बड़ी कंपनियों के विशाल प्लांट मौजूद हैं।

इन कंपनियों के कारण चेन्नई केवल घरेलू बाजार के लिए नहीं, बल्कि निर्यात के लिए भी वाहनों का बड़ा केंद्र बन चुका है। यहां तैयार की गई कारें और कमर्शियल वाहन दुनिया के कई देशों में भेजे जाते हैं। ऑटो सेक्टर के साथ-साथ ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री भी यहां तेजी से विकसित हुई है, जिससे हजारों सहायक उद्योग खड़े हुए हैं। लेकिन चेन्नई की पहचान सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है। यहां रेलवे के डिब्बों का भी बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। Integral Coach Factory, जो चेन्नई में स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माण इकाइयों में से एक है। यहां हर साल हजारों कोच बनाए जाते हैं, जो देशभर की ट्रेनों में लगाए जाते हैं। रक्षा उत्पादन में भी चेन्नई का योगदान तेजी से बढ़ा है। यहां कई रक्षा उपकरण, सैन्य वाहन और एयरोस्पेस कंपोनेंट बनाए जाते हैं। Hindustan Aeronautics Limited और Defence Research and Development Organisation की परियोजनाओं से जुड़े कई उत्पादन केंद्र इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इससे चेन्नई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बन गया है। चेन्नई का चमड़ा और फुटवियर उद्योग भी देशभर में प्रसिद्ध है। यहां बने चमड़े के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी मांग है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी चेन्नई तेजी से उभर रहा है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में यह शहर नई पहचान बना रहा है।

चेन्नई की औद्योगिक सफलता के पीछे उसका समुद्री नेटवर्क भी बड़ी भूमिका निभाता है। यहां तीन प्रमुख बंदरगाह हैं — Chennai Port, Kamarajar Port और Kattupalli Port। ये बंदरगाह आयात और निर्यात को आसान बनाते हैं, जिससे कच्चा माल और तैयार उत्पादों का परिवहन तेज और किफायती होता है। यही वजह है कि विदेशी कंपनियां यहां निवेश करने में रुचि दिखाती हैं।

अगर दूसरे औद्योगिक शहरों से तुलना करें तो Pune ऑटोमोबाइल और आईटी के लिए मजबूत है, Ahmedabad टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री में अग्रणी है, Kanpur चमड़ा और वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, जबकि Indore खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा सेक्टर में तेजी से उभरा है। लेकिन औद्योगिक विविधता और उत्पादन क्षमता के लिहाज से चेन्नई इन सभी से आगे दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी नीतियों ने चेन्नई को और मजबूती दी है। बेहतर सड़क नेटवर्क, रेलवे कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट सुविधा और स्किल्ड वर्कफोर्स ने इसे निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों ने भी विकास को गति दी है। चेन्नई में औद्योगिक विकास का असर रोजगार पर भी साफ दिखता है। लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन फैक्ट्रियों से जुड़े हैं। छोटे उद्योगों और सप्लाई चेन नेटवर्क ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाया है। यही वजह है कि यह शहर केवल तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण भारत की आर्थिक धुरी माना जाता है।

आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी चेन्नई की भूमिका और बढ़ने की संभावना है। कई बड़ी कंपनियां यहां नई यूनिट लगाने की तैयारी में हैं। इससे यह शहर भविष्य की औद्योगिक क्रांति का भी केंद्र बन सकता है। स्पष्ट है कि भारत में यदि किसी शहर को फैक्ट्रियों का असली गढ़ कहा जाए तो चेन्नई का नाम सबसे ऊपर आता है।

डेयरी फार्मर्स को मिली बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। हमारे देश की बड़ी आबादी दूध के कारोबार से जुड़ी है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर छोटे डेयरी कारोबारी होते हैं। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे दूध व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (Milkfed) ने खरीद प्रक्रिया में बदलाव करते हुए, हर एक डेयरी उत्पादक से रोजाना 20 लीटर दूध खरीद की सीमा तय करने का फैसला किया है।

किसे होगा फायदा?

हिमाचल प्रदेश में मिल्कफेड की ओर से सभी दूध उत्पादकों से 20 लीटर दूध खरीदने की सीमा तय की गई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि छोटे डेयरी फार्मर्स को लाभ देने के लिए ये प्लान बनाया गया है, 20 लीटर खरीद सीमा तय करने की बात पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि, सरकार की ओर से बढ़ाई गई MSP का लाभ केवल बड़े डेयरी फार्मर्स तक सीमित ना रह जाए इसलिए ये फैसला लिया गया है।

दूध में बढ़ाई गई तगड़ी MSP

सरकार के इस फैसले के साथ ही प्रवक्ता ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में लगातार दूध उत्पादकों को फायदा पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की ओर से गाय और भैंस के दूध में मिलने वाली MSP पर भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में गाय के दूध की MSP 32 से बढ़ाकर 61 प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह भैंस के दूध में MSP 47 प्रति लीटर से बढ़ाकर 61 प्रति लीटर हो गई है।

दूध कलेक्शन में भी हुई बढ़ोतरी

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में लगातार दूध उत्पादन करने वाले किसानों और पशुपालकों को सपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ रही दूध की कीमतों के कारण पिछले दो सालों में सहकारी प्रणाली में भाग लेने वाले डेयरी फार्मर्स की संख्या 28,645 से बढ़कर 42,500 हो गई है। वहीं बीते 2 सालों में दूध के कलेक्शन में भी तेजी आई है, रोजाना 1.57 लाख लीटर दूध कलेक्शन से बढ़कर 2.20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है।

विकसित भारत 2047 का रोडमैप: सरकारी बैंकों और कंपनियों के निजीकरण पर फिर तेज हुई बहस

नई दिल्ली। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आर्थिक सुधारों को और तेज करने की जरूरत है। इसी कड़ी में Arvind Panagariya ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकारी बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया को फिर से तेज किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यह केवल आर्थिक सुधार का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति का महत्वपूर्ण आधार है। सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान में Columbia University में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया ने स्पष्ट कहा कि भारत को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी कम करनी चाहिए, जहां निजी क्षेत्र अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकता है।

पनगढ़िया ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को विनिवेश कार्यक्रम को गति देने के लिए एक स्वतंत्र निजीकरण मंत्रालय गठित करना चाहिए। उनका कहना था कि मौजूदा विनिवेश विभाग अपेक्षित गति से काम नहीं कर पा रहा है और निजीकरण की प्रक्रिया कई बार प्रशासनिक जटिलताओं में फंस जाती है। ऐसे में यदि एक समर्पित मंत्रालय बनाया जाए तो यह प्रक्रिया अधिक प्रभावी और तेज हो सकती है। उन्होंने कहा कि "विकसित भारत-2047" की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और दक्ष बनाए। इसके लिए सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों और बैंकों के निजीकरण को पुनर्जीवित करना बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि NITI Aayog के नेतृत्व में 2016 में बड़े पैमाने पर निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश की नीति शुरू की गई थी। उस समय पनगढ़िया ही इसके प्रमुख नीति निर्माताओं में शामिल थे।

भारत में निजीकरण का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है। समर्थकों का मानना है कि इससे सरकारी बोझ कम होता है, कंपनियों की कार्यक्षमता बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा में सुधार आता है। वहीं आलोचक कहते हैं कि इससे रोजगार पर असर पड़ सकता है और रणनीतिक क्षेत्रों में सरकार का नियंत्रण कमजोर हो सकता है। लेकिन पनगढ़िया का तर्क है कि सरकार को उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जहां उसकी वास्तविक भूमिका जरूरी है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा।

इंदौर का मेगा ग्रीन प्लान

2.81 लाख पौधे, तालाब और चेकडैम से बढ़ेगा भूजल स्तर

इंदौरः शहर को हरियाली और जल संरक्षण की दिशा में मजबूत करने के लिए बड़ा मेगा ग्रीन प्लान तैयार किया गया है।

योजना के तहत शहर में 2.81 लाख पौधे लगाए जाएंगे और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नए तालाबों का निर्माण तथा चेकडैम बनाए जाएंगे, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा। जानकारी के अनुसार, नगर निगम और प्रशासन मिलकर इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। इसके तहत खाली भूमि, सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही बारिश के पानी को रोकने के लिए जल संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर में हरियाली बढ़ाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और गिरते भूजल स्तर को सुधारना है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में यह पहल इंदौर को एक और मजबूत ग्रीन सिटी मॉडल के रूप में स्थापित करेगी।

एमवाय हॉस्पिटल ने रचा इतिहासः सड़क हादसे में नष्ट हुई मूत्रनली का आंत से किया पुनर्निर्माण

इंदौर। इंदौर के एमवाय अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के डॉक्टरों ने एक ऐसे युवक की मूत्रनली (यूरेथ्रा) का सफल पुनर्निर्माण किया है, जिसकी यूरेथ्रा सड़क दुर्घटना में पूरी तरह नष्ट हो गई थी। यह जटिल सर्जरी "एंटेरो यूरेथ्रोप्लास्टी" तकनीक से की गई, जिसे मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहली बार सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है।डॉक्टरों के अनुसार, युवक करीब ढाई साल पहले एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था। हादसे में उसकी मूत्रनली पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना के बाद उसने कई अस्पतालों में इलाज कराया और अलग-अलग चिकित्सकीय प्रक्रियाओं से गुजरा, लेकिन उसे सामान्य रूप से मूत्र त्याग करने में सफलता नहीं मिली। वह लंबे समय से सुपराप्यूबिक कैथेटर (एसपीसी) के सहारे जीवन व्यतीत कर रहा था। बाद में मरीज एमवाय अस्पताल पहुंचा, जहां विशेषज्ञों की टीम ने उसकी विस्तृत जांच और मूल्यांकन किया।

इस तकनीक से हुई सफल सर्जरी

जांच के बाद डॉक्टरों ने एंटेरो यूरेथ्रोप्लास्टी तकनीक से यूरेथ्रा का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। इस तकनीक में आंत के एक हिस्से को उसके रक्त प्रवाह के साथ सुरक्षित निकालकर मूत्रनली के क्षतिग्रस्त हिस्से की जगह प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे मूत्र का सामान्य मार्ग दोबारा स्थापित किया जा सके।

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, यह सर्जरी अत्यंत जटिल और उच्च विशेषज्ञता वाली मानी जाती है और गंभीर चोटों या लंबी यूरेथ्रल क्षति वाले मरीजों के लिए अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग की जाती है।

शराब दुकान विवाद में सीएम से गुहार के बाद एक्शनः जिला प्रशासन ने दुकान को किया सील

इंदौर। शहर में बंगाली चौराहा स्थित शराब दुकान को लेकर हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। मारपीट का आरोप लगाने वाली महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने कहा कि सिर्फ "स्वच्छ इंदौर" नहीं, बल्कि "सुरक्षित इंदौर" का नारा भी दिया जाना चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शराब दुकान को सील कर दिया है।

वहां होने वाली गतिविधियों पर सवाल उठाए 'किष्किंधा अपार्टमेंट निवासी महिला कविता रोकड़े ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर शराब दुकान के पास संचालित कथित अवैध अहाते और वहां होने वाली गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। महिला का आरोप है कि शराब दुकान के बाहर लोग खुलेआम शराब पीते हैं, सड़क पर विवाद करते हैं और क्षेत्र का माहौल खराब करते हैं। महिला का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब वे अन्य महिलाओं के साथ मौके पर वीडियो बनाने पहुंचीं तो उनके साथ मारपीट और धक्का-मुक्की की गई। मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की थी वीडियो में महिला ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद पहुंचे कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें एफआईआर दर्ज कराने से हतोत्साहित किया। महिला के अनुसार पुलिसकर्मियों ने कहा कि आरोपी प्रभावशाली और पैसे वाले लोग हैं, जो जल्द ही छूट जाएंगे। इस बयान के बाद महिला ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। महिला ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अपील करते हुए कहा कि इंदौर को केवल स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी बनाया जाए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक गोपाल गावंडे द्वारा पंकज प्रिंटर्स एण्ड पैकेजिंग एल.यू.एन 22 सेक्टर एफ सांवेर रोड़, इण्डस्ट्रीयल एरिया इंदौर म.प्र. एवं जी -1 कॉस्मिक रीजेंसी 117 गोकुल नगर कनाडिया इंदौर म.प्र. से प्रकाशित
संपादक गोपाल गावंडे (पी.आर.बी.) एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार (सभी विवादो का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)